The Pioneer
7-1-2023

National workshop on agroforestry & farm forestry concludes at FRI

PNS ■ DEHRADUN

The two-day national workshop on agroforestry and farm forestry for sustainable land management under the World Bank funded ecosystem services improvement project concluded at the Forest Research Institute on Saturday. Experts from national and international organisations, key ministries of the Central government, State Forest departments, forestry and agricultural research institutions of the country, non-governmental organisations, universities, wood-based industries and farmers participated in the workshop and shared their experiences, research findings and best practices for promotion of agroforestry and farm forestry for sustainable land and ecosystem management. During the workshop 24 presentations were made by experts for promotion of agroforestry and farm forestry in the country. Progressive farmers and representatives of the wood-based industries participated in the panel discussion on opportunities and barriers for promotion of agroforestry in India. They shared their experiences and challenges faced in adoption and scaling up of agroforestry and farm forestry practices.

After deliberations and experience sharing, the national workshop concluded with finalisation of the doable and practical recommendations and solutions for promotion of agroforestry with respect to availability of quality planting materials of agroforestry species for different agroclimatic zones, rationalisation of policies and regulatory regimes for development of agroforestry and farm forestry, certification framework and market mechanism for agroforestry and farm forestry produces.

Dainik Jagran
7-1-2023

कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए सुझाए उपाय

- विश्व बैंक की ओर से वित्त पोषित परितंत्र सेवाएं सुधार परियोजना के तहत कृषि वानिकी पर आयोजित की गई कार्यशाला
- एफआरआइ में आयोजित कार्यशाला में बाधाओं और चुनौतियों से निपटने के लिए की गई चर्चा

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के महानिदेशक अरुण सिंह रावत • जागरण

जागरण संवाददाता, देहरादून: भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने विश्व बैंक की वित्तपोषित पारितंत्र सेवाएं सुधार परियोजना के तहत दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों ने अपनी प्रस्तुतियों से सुझाव दिए। साथ ही बाधाओं और चुनौतियों से निपटने के लिए नवीनतम जानकारी प्रदान की गई।

शुक्रवार को कार्यशाला के समापन दिवस पर अनुसंधान के महानिदेशक अरुण सिंह रावत और वरिष्ठ पर्यावरण सलाहकार डा. अनुपम जोशी ने कार्यशाला के आयोजन के लिए समस्त विशेषज्ञों, प्रतिनिधियों और आयोजकों के योगदान की सराहना की। कार्यशाला में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों, भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों, राज्य के वन विभागों, देश के वानिकी और कृषि अनुसंधान संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों ने अपने अनुभव साझा किए। स्थायी भूमि और पारितंत्र प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान के परिणामों, अनुभवों और उच्च प्रणालियों को साझा किया गया। प्रगतिशील किसानों और लकड़ी आधारित उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भारत में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के अवसरों और बाधाओं पर पैनल चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कृषि वानि प्रथाओं को अपनाने और बढ़ाने अपने अनुभव साझा किए हैं। कृ वानिकी को बढ़ावा देने को जलवायु क्षेत्रों के लिए कृषि वानि प्रजातियों की गुणवत्ता रोपण साम की उपलब्धता पर जोर दिया गया।

Dainik Jagran
6-1-2023

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 15 प्रतिशत पचा जाते हैं वन

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित कार्यशाला का दीप जलाकर उद्घाटन करते मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी वन अकादमी के निदेशक भरत ज्योति, वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक डा. रेणु सिंह, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के महानिदेशक अरुण सिंह रावत • जागरण

- कृषि वानिकी के क्षेत्र में अपेक्षित विकास के बूते राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की पूर्ति पर बल
- आइसीएफआरई में राष्ट्रीय कार्यशाला में जुटे देशभर के विशेषज्ञ तैयार कर रहे रणनीति

जागरण संवाददाता, देहरादून: भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आइसीएफआरई) विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से पारितंत्र सेवाओं में सुधार के लिए सतत भूमि प्रबंधन की दिशा में काम कर रही है। यह ऐसा भूमि प्रबंधन होगा, जिसके बूते कृषि वानिकी क्षेत्र के लिए नई संभावनाएं विकसित की जा सकेंगी। इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए आइसीएफआरई दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में रणनीति/ फ्रेमवर्क तैयार करने में जुट गई है।

गुरुवार को दो दिवसीय कार्यशाला का उदघाटन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के निदेशक भरत ज्योति ने किया। उन्होंने कहा कि कृषि वानिकी के लिए परिवर्तनकारी कार्रवाई की जरूरत है। साथ ही बहुपादपीय कृषिकरण के सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाकर लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। वहीं, आइसीएफआरई के महानिदेशक एएस रावत ने कहा कि वन क्षेत्र भारत में कार्बन डाइआक्साइड का शुद्ध सिंक हैं। इसी क्षमता के बूते यह ग्रीनहाउस गैसों का 15 प्रतिशत हिस्सा पचा लेते हैं। यदि कृषि वानिकी के माध्यम से हरियाली को बढ़ाया जाए तो यह गेमचेंजर हो सकते हैं। कृषि वानिकी के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने के साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की पूर्ति की जा सकती है। कार्यशाला में विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों ने कृषि वानिकी की राह को सुगम करने के लिए सुझाव दिए। साथ ही शोधपत्र भी प्रस्तुत किए गए। कार्यशाला में एफआरआइ की निदेशक डा रेणु सिंह, विश्व बैंक के वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ डा अनुपम जोशी ने भी विचार रखे। कार्यक्रम में आइसीएफआरई की उपमहानिदेशक कंचन देवी समेत 200 विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया।

Shah Times
6-1-2023

सतत भूमि प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी पर राष्ट्रीय कायर्शाला

शाह टाइम्स संवाददाता

देहरादून। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्, देहरादून विश्व बैंक ने वित्त पोषित पारितंत्र सेवाएं सुधार परियोजना के तहत सतभूमि प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी पर राष्ट्रीय कायशाला का आयोजन कर रही है।

राष्ट्रीय कायशाला का उद्देश्य उपयुक्तरण नीतियों/फ्रेमवर्क को विकसित करना और कृषि वानिकी के विकास के लिए मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने और भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों और अंतराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की प्राप्ति में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार को आवश्यक नीतिगत इनपुट प्रदान करना है। मरुस्थली करण और भूमि क्षरण से तत्विकास लक्ष्यों का मुकाबला करना, और भारत को एक अभिनव, संसाधन कुशल और काबर्न तटस्थ व्यवस्था की ओर स्थानांतरित करना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय

आईसीएफआरई ने किया आयोजन

संगठनों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, पयार्वरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पयार्वरण, वन और जलवायु परिवतन मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य के वन विभाग, देश के वानिकी और कृषि अनुसंधान संस्थान, गैर-सरकारी देश के विभिन्न हिस्सों से संगठन, विश्व, विद्यालय, लकड़ी आधारित उद्योग और किसान कायशाला में भाग ले रहे हैं और स्थायी भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त रूप रेखा तैयार करने में अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। डॉ. रेणु सिंह, निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान ने कायशाला के मुख्य अतिथि और राष्ट्रीय कायशाला के सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया और स्वागत भाषण में राष्ट्रीय कायशाला की संरचना एवं कृषि वानिकी के महत्व पर जानकारी दी।

विश्व बैंक के वरिष्ठ पयार्वरण विशेषज्ञ डॉ. अनुपम जोशी ने कहा कि कृषि वानिकी देश के प्राकृतिक वन आवरण के संरक्षण के साथ-साथ देश के सकल घरेलू उत्पाद में वन और वृक्षों के आवरण के योगदान को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण 'प्रकृति-आधारित समाधानों में से एक है। कृषि वानिकी जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों से निपटने में भूमि क्षरण को रोकने और जैवविविधता संरक्षण के लिए वन पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य सुधार में अहम योगदान प्रदान करेगा।

निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भरत ज्योति ने कायशाला के मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि वन पारितंत्र के प्राकृतिक संतुलन को बनाने में अहम है और देश में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिवर्तनकारी कारवाई करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए बहुपादपीय कृषि करण के सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। जोकि एक सतत् विकास में अहम योगदान प्रदान करेंगें।

Janbharat Mail
7-1-2023

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् द्वारा सतत भूमि प्रबंधन के लिए कृषिवानिकी पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

देहरादून, संवाददाता। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून नेविश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित पारितंत्र सेवाएं सुधार परियोजना के तहत उपयुक्त रणनीतियों/फ्रेमवर्क को विकसित करने के लिए कृषि वानिकी पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है और पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय लक्ष्यों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए देश में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिए भारत सरकार को नीतिगत जानकारी प्रदान की गई।

कार्यशाला में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों, राज्य के वन विभागों, देश के वानिकी और कृषि अनुसंधान संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, लकड़ी आधारित उद्योगों के प्रतिनिधियों और किसानों ने भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। स्थायी भूमि और पारितंत्र प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान के परिणामों, अनुभवों और सर्वोत्तम प्रणालियों को कार्यशाला के दौरान साझा किया गया। देश में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों द्वारा 24 प्रस्तुतियां दी गईं। प्रगतिशील किसानों और लकड़ी आधारित उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भारत में कृषि-वानिकी को बढ़ावा देने के अवसरों और बाधाओं पर पैनल चर्चा में भाग लिया। उन्होंने कृषि वानिकी प्रथाओं को अपनाने और बढ़ाने में अपने अनुभव और चुनौतियों को साझा किया है।

दो दिनों के विचार-विमर्श और अनुभव साझा करने के बाद, राष्ट्रीय कार्यशाला ने कृषिवानिकी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए कृषि वानिकी प्रजातियों की गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता, नीतियों के युक्तिकरण और कृषि वानिकी के विकास के लिए नियामक व्यवस्थाओं के संबंध में और कृषि वानिकी, प्रमाणन ढांचा और कृषि वानिकी उत्पादों के लिए बाजार तंत्रविकसित करने और व्यावहारिक सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है।

श्री अरुण सिंह रावत, महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् और डॉ अनुपम जोशी, वरिष्ठ पर्यावरण समाजवादी ने राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन सत्र की अध्यक्षता की औरकार्यशाला के सफल आयोजन हेतु समस्त विशेषज्ञों, प्रतिनिधियों और आयोजकों के योगदान की सराहना की। यह भी कहा की कार्यशाला की संस्तुतियाँ कृषि वानिकी को बढ़ावा देने में अहम योगदान प्रदान करेंगें, जो कि देश के हरित आवरण को बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि एवं राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को 2030 तक पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होंगें।

Times of India
6-1-2023

ICFRE organises 2-day national workshop on agro, farm forestry

Dehradun: The Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) is organising a two-day national workshop on agroforestry and farm forestry for sustainable land management under the world bank funded Ecosystem Services Improvement Project at Dehradun from Thursday.

The objective of the workshop is to develop a suitable framework and to provide policy inputs to the government for addressing issues and challenges for the development of agroforestry and farm forestry. Eminent experts from the country are participating in the workshop. **Shivani Azad**

Rashtriya Sahara
6-1-2023

किसानों की आय दोगुना करने के लिए है कृषि वानिकी जरूरी

सहारा न्यूज ब्यूरो

देहरादून।

भारतीय वानिकी परिषद व शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) द्वारा विश्व बैंक से वित्त पोषित पारितंत्र सेवाएं सुधार परियोजना के तहत सतत भूमि प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

आईसीएफआरई में आयोजित की गई कृषि वानिकी आधारित कार्यशाला

कार्यशाला का उद्देश्य उपयुक्त रणनीतियों-फ्रेमवर्क को विकसित करना और कृषि वानिकी के विकास के लिए मुद्दों व चुनौतियों का समाधान कर कृषि वानिकी को बढ़ावा देना है।

एफआरआई के सभागार में आयोजित कार्यशाला में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के निदेशक भरत ज्योति ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्जवलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वन पारितंत्र के प्राकृतिक संतुलन को बनाने में अहम हैं।

कहा कि देश में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिवर्तनकारी कदम उठाने की जरूरत है। कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए बहु पादपीय कृषिकरण के सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता भी है। आईसीएफआरई के महानिदेशक अरुण सिंह रावत ने कहा कि वन क्षेत्र भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्ध सिंक है जो देश के कुल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का 15 फीसद ऑफसेट करते हैं।

उन्होंने कहा कि कृषि वानिकी देश के हरित क्षेत्र को बढ़ाने और किसानों की आय दोगुना करने के लिए भी वास्तविक गेम चेंजर है। इससे लकड़ी आधारित उद्योगों की मांग भी पूरी होगी। विश्व बैंक के पर्यावरण विशेषज्ञ डा. अनुपम जोशी ने कहा कि कृषि वानिकी देश के प्राकृतिक वन आवरण के संरक्षण के साथ देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने व भूक्षरण को रोकने में भी मददगार साबित होगा। इससे पहले एफआरआई की निदेशक डा.रेणु सिंह ने कार्यशाला में शिरकत कर रहे अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कृषि वानिकी पर आधारित कार्यश्रला के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। उप महानिदेशक कंचन देवी ने धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया। कार्यशाला में देशभर के दो सौ से अधिक विशेषज्ञ, उद्यमी व कृषक प्रतिभाग कर रहे हैं।

कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर मंचासीन अतिथि।

Encounter Samachar
6-1-2023

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् द्वारा सतत भूमि प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी पर राष्ट्रीय कायर्शाला का आयोजन

(ब्यूरो एनकाउंटर समाचार)

देहरादून। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून विश्वबैंक द्वारा वित्त पोषित पारितंत्र सेवाएं सुधार परियोजना के तहत सतत्भूमि प्रबन्धन के लिए कृषि वानिकी पर राष्ट्रीय कायर्शाला का आयोजन कर रही है। राष्ट्रीय कायर्शाला का उद्देश्य उपयुक्तरण नीतियोंक्रेम वर्क्स विकसित करना और कृषि वानिकी के विकास के लिए मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने और भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों और अंतरार्ष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की प्राप्ति में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार को आवश्यक नीतिगत इन पुट प्रदान करना है।

मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण और सतत्विकास लक्ष्यों का मुकाबला करने, और भारत को एक अभिनव, संसाधनकुशल और कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरित करना है। राष्ट्रीय औरअंतरर्ष्ट्रीय संगठनों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, पयार्वरण, वन और जलवायु परिवतर्न मंत्रालय, भारत सरकार, पयार्वरण, वन और जलवायु परिवतर्न मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य के वन विभाग, देश के वानिकी और कृषिअनुसंधन संस्थान, गैर–सरकारी देश के विभिन्न हिस्सों से संगठन, विश्वविद्यालय, लकड़ी आधारित उद्योग और किसान कायर्शाला में भागले रहे हैं और स्थायी भूमि और पारिस्थिति की तंत्र प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त रूपरेखा तैयार करने में अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।

डॉ. रेणु सिंह, निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान ने कायर्शाला के मुख्य अतिथि और राष्ट्रीय कायर्शाला के सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया, और स्वागत भाषण में राष्ट्रीय कायर्शाला की संरचना एवं कृषि वानिकी के महत्व पर जानकारी दी।

विश्वबैंक के वरिष्ठ पयार्वरण विशेषज्ञ डॉ. अनुपम जोशी ने कहा कि कृषि वानिकी देश के प्राकृतिक वन आवरण के संरक्षण के साथ–साथदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वन और वृक्षों के आवरण के योगदान को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण

प्रकृति–आधारित समाधानों में से एक है। कृषि वानिकी जल वायु परिवतर्न के जुखेरिमों से निपटने में भूमिक्षरण को रोकने और जैव विविधता संरक्षण के लिए वन पारिस्थिति की तंत्र के स्वास्थ्य सुधार में अहम योगदान प्रदान करेगा।

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के महानिदेशक अरुण सिंह रावत ने उद्घाटन सत्र के संबोधन में कहा कि वन क्षेत्र भारत में कार्बनडाइ ऑक्साइड का शुद्ध सिंक है और भारत के कुलग्रीन हाउस गैस के उत्सजर्न का 15%ऑफ सेट करतेहैं और वन अपेक्षा कृतअन्य महत्वपूर्णसह–लाभों के साथ कमलागत पर जलवायु परिवतर्न शमन अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कृषिवानिकी देश के हरित क्षेत्र को बढ़ाने, किसानों को दो गुना करने में वास्तविक गेमचेंजर है। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि वानिकी देश के हरित आवरण को बढ़ाने, किसानों की आय को दो गुना करने, लकड़ी आधारित उद्योगों की मांगों को पूरा करने के साथ–साथ राष्ट्रीय लक्ष्यों और अंतरर्ष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभातेहैं। राष्ट्रीय स्तर पर निधारित योगदान (एनडीसी) वानिकी क्षेत्र लक्ष्य, भूमि क्षरण तटस्थता लक्ष्य, वैश्विक जैव विविधता लक्ष्य और सततविकास लक्ष्य को प्राप्त करना है। उन्होंने स्थायी भूमि और पारिस्थिति की तंत्र प्रबंधन में इस कायर्शाला के महत्व पर प्रकाश डाला

भरत ज्योति निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी ने कायर्शाला के मुख्य अतिथि के रूपमें अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि वन पारितंत्र के प्राकृतिक संतुलन को बनाने मेंअहम हैऔर देश में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिवतर्नकारी कारर्वाई करने की आवश्यकताहै। उन्होंने यह भीकहा कि कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए बहुपादपीय कृषिकरण के सवोर्त्तम प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। जो कि एक सतत् विकास मेंअहम योगदान प्रदान करेंगें।

The Hawk
6-1-2023

National Workshop On Agroforestry, Farm Forestry For Sustainable Land Management By ICFRE Organised At Dehradun 5-6 January 23

Dehradun (The Hawk): Indian Council of Forestry Research and Education is organising a national workshop on agroforestry and farm forestry for sustainable land management under the world bank funded Ecosystem Services Improvement Project at Dehradun. The objective of this workshop to develop the suitable strategies/ frameworks and to provide policy inputs to the Government for addressing issues and challenges for development of agroforestry and farm forestry, and achieving India's national targets and international commitments related to climate change, biodiversity conservation, combating desertification and land degradation and sustainable development goals. Eminent experts from national and international organisations, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, State Forest Departments, forestry and agricultural research institutions of the country, non-governmental organisations, universities, wood-based industries and farmers from various parts of the country are participating in the workshop and sharing their experience in framing the suitable frameworks for promotion of agroforestry and farm forestry for sustainable land and ecosystem management.

Dr.Renu Singh, Director, Forest Research Institute welcomed the Chief Guest of the Workshop and all the delegates of the national workshop and briefed the structure of the national workshop.

Dr. Anupam Joshi, Senior Environment Specialist from the World Bank stated that agroforestry is one of the important nature-based solutions for conservation of natural forest cover of the country as well as enhancing the contribution of forest and tree cover in the GDP of the country as well as to improve the health of forest ecosystem for addressing the issue of climate change, combating land degradation and biodiversity conservation.

Sh. Arun Singh Rawat, Director General of Indian Council of Forestry Research and Education in his address stated that Forest sector is net sink of carbon dioxide in India and removed 15% of the India's greenhouse gas emissions, and forests provide climate change mitigation opportunity at relatively lower costs along with other significant co-benefits. He also stated that agroforestry and farm forestry is the real game changer in increasing the green cover of the country, doubling the farmers income, fulfilling the demands of the wood-based industries as well as play an important role in achieving national targets and international commitments of nationally determined contribution (NDC) forestry sector target, land degradation neutrality targets, global biodiversity goals and sustainable development goals. He also stated that agroforestry and farm forest play an important role in shifting India towards an innovative, resource efficient and carbon neutral economy.He highlighted the importance of this workshop in developing suitable strategies for sustainable management of land resouces.

Sh. Bharat Jyoti, Director, Indira Gandhi National Forest Academy stated in his inaugural address as a Chief Guest of the workshop stated that natural forests are safeguarding the ecological balance and some transformative actions need to be taken for promotion of agroforestry and farm forestry in the country. He also stated that polyculture practices need to be adopted promotion of the agroforestry and farm forestry.

The workshop is comprised of the four technical sessions on 'Agroforestry and farm forestry practices for sustainable land and ecosystem management', 'Quality planting materials for scaling up of agroforestry and farm Forestry practices', 'Rationalization of policies and regulatory regimes for development of agroforestry and farm forestry', 'Certification framework and market mechanism for agroforestry and farm forestry', Parallel session on 'Knowledge sharing and learning session for scaling up of agroforestry and farm forestry practices for sustainable land and ecosystem management in the form of exhibition, poster presentation and documentaries' are being conducted in this national workshop. Ms. Kanchan Devi, Director (International Cooperation) and Project Director, ESIP, ICFRE has proposed a formal vote of thanks in the inaugural session of the national workshop.About 200 delegates form various parts of the country, national and international organisations, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, State Forest Departments, universities, NGOs, wood-based industries and farmers are participating in this national workshop.

Uttarbharat Live
7-1-2023

देश में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने पर जोर

दो दिवसीय कृषि वानिकी पर राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन

उत्तर भारत लाइव ब्यूरो
uttarbharatlive.com

- चुनौतियों को दूर करने के लिए भारत सरकार जानकारी प्रदान की गई
- कसानों की आय में वृद्धि 2030 तक सहायक सिद्ध होंगे

देहरादून। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून ने विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित पारितंत्र सेवाएं सुधार परियोजना के तहत उपयुक्त रणनीतियों/फ्रेमवर्क को विकसित करने के लिए कृषि वानिकी पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। और पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय लक्ष्यों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए देश में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिए भारत सरकार को नीतिगत जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों, राज्य के वन विभागों, देश के वानिकी और कृषि अनुसंधान संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, लकड़ी आधारित उद्योगों के प्रतिनिधियों और किसानों ने भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। स्थायी भूमि और पारितंत्र प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान के परिणामों, अनुभवों और सर्वोत्तम प्रणालियों को कार्यशाला के दौरान साझा किया गया। देश में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों द्वार 24 प्रस्तुतियां दी गई। प्रगतिशील किसानों और लकड़ी आधारित उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भारत में कृषिवानिकी को बढ़ावा देने के अवसरों और बाधाओं पर पैनल चर्चा में भाग लिया। उन्होंने कृषि वानिकी प्रथाओं को अपनाने और बढ़ाने में अपने अनुभव और चुनौतियों को साझा किया है। दो दिनों के विचार-विमर्श और अनुभव साझा करने के बाद, राष्ट्रीय कार्यशाला ने कृषिवानिकी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए कृषि वानिकी प्रजातियों की गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता, नीतियों के युक्तिकरण और कृषि वानिकी के विकास के लिए नियामक व्यवस्थाओं के संबंध में और कृषि वानिकी, प्रमाणन ढांचा और कृषि वानिकी उत्पादों के लिए बाजार तंत्रविकसित करने और व्यावहारिक सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है। अरुण सिंह रावत, महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् और डॉ अनुपम जोशी, वरिष्ठ पर्यावरण समाजवादी ने राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन सत्र की अध्यक्षता की औरकार्यशाला के सफल आयोजन हेतु समस्त विशेषज्ञों, प्रतिनिधियों और आयोजकों के योगदान की सराहना की। यह भी कहा की कार्यशाला की संस्तुतियाँ कृषि वानिकी को बढ़ावा देने में अहम योगदान प्रदान करेंगें, जो कि देश के हरित आवरण को बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि एवं राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को 2030 तक पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होंगें।

Indian Express
8-1-2023

Indian Council of Forestry Research and Education organizes a national workshop at Dehradun.

Indian Council of Forestry Research and Education is organising a national workshop on agroforestry and farm forestry for sustainable land management under the world bank funded Ecosystem Services Improvement Project at Dehradun. Eminent experts from national and international organisations, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, State Forest Departments, forestry and agricultural research institutions of the country, non-governmental organisations, universities, wood-based industries and farmers from various parts of the country are participating in the workshop and sharing their experience in framing the suitable frameworks for promotion of agroforestry and farm forestry for sustainable land and ecosystem management. Dr.Renu Singh, Director, Forest Research Institute welcomed the Chief Guest of the Workshop and all the delegates of the national workshop and briefed the structure of the national workshop.

Rashtriya Sahara
7-1-2023

कार्यशाला में प्रस्तुत किए 24 शोध पत्र

देहरादून (एसएनबी)। भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) द्वारा सतत भूमि प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन शुक्रवार को हुआ।

परिषद के महानिदेशक अरुण सिंह रावत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। एफआरआई के सभागार में आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे विशेषज्ञों ने कृषि वानिकी के विकास के लिए मुद्दों व चुनौतियों के समाधान पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। साथ ही पारितंत्र प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान के परिणामों, अनुभवों व प्रणालियों को साझा किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा 24 शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए। कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए कृषि वानिकी प्रजातियों की गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता, नीतियों के युक्तिकरण व कृषि वानिकी के विकास के लिए नियामक व्यवस्थाओं के संबंध में प्रमाणन ढांचा व कृषि वानिकी उत्पादों के लिए बाजार तंत्र विकसित करने के लिए व्यवहारिक सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया। एफआरआई की निदेशक डा. रेणु सिंह ने उम्मीद जताई कि कार्यशाला के निष्कर्ष कृषि वानिकी को आगे बढ़ाने के लिए मददगार साबित होंगे।

माडलों का अवलोकन करते लोग।

Shah Times
7-1-2023

कृषि वानिकी पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

शाह टाइम्स संवाददाता

देहरादून। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून ने विश्व बैंक से वित्तपोषित पारितंत्र सेवाएं सुधार परियोजना के तहत उपयुक्त रणनीतियों/फ्रेमवक ंको विकसित करने के लिए कृषि वानिकी पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कायर्शाला का आयोजन किया है और पयार्वरण से संबंधित राष्ट्रीय लक्ष्यों और अंतराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए देश में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिए भारत सरकार को नीतिगत जानकारी प्रदान की गई।

कायर्शाला में राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय संगठनों, भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों, राज्य के वन विभागों, देश के वानिकी और कृषि अनुसंधान संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, लकड़ी आधारित उद्योगों के प्रतिनिधियों और किसानों ने भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। स्थायी भूमि

■ भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान में हुआ सेमिनार

और पारितंत्र प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान के परिणामों, अनुभवों और सवोर्त्तम प्रणालियों को कायर्शाला के दौरान साझा किया गया। देश में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों ने 24 प्रस्तुतियां दी। प्रगतिशील किसानों और लकड़ी आधारित उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भारत में कृषिवानिकी को बढ़ावा देने के अवसरों और बाधाओं पर पैनल चर्चा में भाग लिया। उन्होंने कृषि वानिकी प्रथाओं को अपनाने और बढ़ाने में अपने अनुभव और चुनौतियों को साझा किया है। अरुण सिंह रावत, महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् और डॉ अनुपम जोशी, वरिष्ठ पयार्वरण समाजवादी ने राष्ट्रीय कायर्शाला के समापन सत्र की अध्यक्षता की।

I-Next (Dainik Jagran)
6-1-2023

मंथन आईसीएफआरई मे वर्कशॉप, जुटे देशभर के एक्सपर्ट

ग्रीनहाउस गैस एमिशन का 15 परसेंट हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं फॉरेस्ट रीजंस

एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री के जरिए हरियाली को बढ़ाया जाए तो बनेंगे गेमचेंजर

dehradun@inext.co.in

DEHRADUN (5 Jan): भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से पारितंत्र सेवाओं में सुधार के लिए सतत भूमि प्रबंधन की दिशा में काम कर रही है. यह ऐसा भूमि प्रबंधन होगा, जिसके बूते कृषि वानिकी क्षेत्र के लिए नई संभावनाएं विकसित की जा सकेंगी. इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए आईसीएफआरई दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में रणनीति/फ्रेमवर्क तैयार करने में जुट गई है.

टारगेट हो सकता है अचीव

गुरुवार को दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के निदेशक भरत ज्योति ने किया. उन्होंने कहा कि कृषि वानिकी के लिए परिवर्तनकारी कार्रवाई की जरूरत है. साथ ही बहुपादपीय कृषिकरण के सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाकर लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं. वहीं, आईसीएफआरई के महानिदेशक एएस रावत ने कहा कि वन क्षेत्र भारत में कार्बन डाईआक्साइड का शुद्ध सिंक है. इसी क्षमता के बूते यह ग्रीनहाउस गैसों का 15 प्रतिशत हिस्सा पचा लेते हैं. यदि कृषि वानिकी के माध्यम से हरियाली को बढ़ाया जाए तो यह गेमचेंजर हो सकते हैं.

एक्सपर्ट्स ने दिए सुझाव

कृषि वानिकी के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने के साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की पूर्ति की जा सकती है. कार्यशाला में विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों ने कृषि वानिकी की राह को सुगम करने के लिए सुझाव दिए. साथ ही शोधपत्र भी प्रस्तुत किए गए. कार्यशाला में एफआरआई की निदेशक डॉ. रेणु सिंह, विश्व बैंक के वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. अनुपम जोशी ने भी विचार रखे. कार्यक्रम में आईसीएफआरई की उपमहानिदेशक कंचन देवी समेत 200 विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया.

Amar Ujala
6-1-2023

कृषि वानिकी पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

देहरादून। कृषि वानिकी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही इससे भू-कटाव को रोकने में भी मदद मिलेगी। यह बात विश्व बैंक के वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम जोशी ने कही। बृहस्पतिवार को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की ओर से कृषि वानिकी पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। परिषद के महानिदेशक अरुण सिंह रावत ने कहा कि वन कई महत्वपूर्ण लाभों के साथ कम लागत पर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। मा.सि.रि.